ject implemented without further loss of time so that the economy of the backward State may get a boost for development. They should also take immediate steps to start weekly cargo steamer service with coordinated road transport service between Calcutta and Karimganj which will serve Tripura, Cachar, Mizoram and adjoining areas which are now very backward and neglected.

The Railway Minister is here.

MR. SPEAKER: That is not the practice. It is open to him to answer if he wants I cannot compel him to answer.

SHRI JYOTIRMOY BOSU: The Railway Minister wanted to make a statement but because he thought that this will come up after lunch, he had gone. Don't you recognise Mr. Sheo Narain as Minister?

MR. SPEAKER: The rule is : if the Minister wants to answer, he may answer. I cannot compel him.

SHRI JYOTIRMOY BOSU: He wants to answer.

MR. SPEAKER: I do not know. Dr. Subramaniam Swamy.

(ii) Appointment of an Air Accident Investigation Commission

DR. SUBRAMANIAM SWAMY (Bombay North-East): Sir, I am quoting from a news item in the Times of India yesterday: Government has reversed its decision to set up an air accident investigation commission. I should like to point out that air crashes have taken place in the last few years and finally it was found on inquiry that the human factor was the most important. I have information which tends to suggest that the main reason why these crashes take place is that senior experienced pilots are cornering most of the flying hours because by this they enhance their pay packets and junior pilots are complaining greatly about this. Most of the safety regulations of the International Civil Aviation Organisation are being flouted in the Indian Airlines and the senior officers continue to function as if it is a private airline. Therefore I urge a thorough probe into it and the amount of time being made available to pilots who fly aircraft. Since the advent of the airbus, senior pilots are flying airbuses for about 50—60 hours a week and it is a clear violation of all regulations. Junior pilots are not getting beyond the flight of some aircraft; they are being made to fly locally and are grossly underutilised. Flying passengers should thank God that more crashes are not taking place; God is kind to this country even if we are not kind to ourselves. I think a thorough probe into the manner in which flights are being scheduled and the allocation of time for pilots will reveal that the Indian Airlines is functioning in an anarchic manner and a thorough probe is necessary.

SHRI JYOTIRMOY BOSU: I have given a short notice question and a call attention on this issue.

MR. SPEAKER: On every subject you have got questions. What am I to do?

SHRI JYOTIRMOY BOSU: If a short notice question had been admitted, it will come up and reply will come. Under 377 no reply is there.

(iii) Working of Textile Corporation, Madhya Pradesh

श्री हुकम चन्द कछवाय (उज्जैन) : अध्यक्ष महोदय, नियम 377 के अधीन मैं जिस विषय को उठा रहा हूं ज्यादा अच्छा यह होता कि इस विषय से सम्बन्धित उद्योग मंत्री यहां उपस्थित रहते, तो उन्हें बहुत सी बातें सुनने को मिलतीं।

[हुक्म चन्द कछवाय]

वस्त्र उद्योग निगम, मध्य प्रदेश द्वारा जो इस समय नीति अपनाई गई है, उसके कारण मध्य प्रदेश की 7 कपड़ा मिलें बहुत बड़े पैमाने पर घाटे में चल रही हैं। इस निगम के चेयरमन श्री एन० पी० श्रीवास्तव हैं, जिनके द्वारा गलत पालिसी अपनाने के कारण ही यह घाटे में चल रही हैं।

निर्यात पालिसी में बहुत त्रुटियां हैं। कपड़ा किस प्रकार से बेचा जाता है, मैं इस के कुछ उदाहरण देना चाहता हूं।

मैसर्ज आर० जे० वुड, बम्बई को, ईरान को एक्सपोर्ट के लिए 14 लाख मीटर कपड़ा दिया गया, जिसका विवरण यह है : 22/28, 60/52, और 89 से० सी०। यह कपड़ा 2-20 रुपये मीटर की दर से बेचा गया, जब कि बाजार-भाव 3-20 रुपये मीटर था। इस प्रकार चेयरमैन, श्रीवास्तव द्वारा इन मिलों को लाखों रुपयों का घाटा कराया जा रहा है।

इतना ही नहीं, आप को यह सुन कर आश्चर्य होगा कि जिन पार्टियों को कपड़ा बेचा गया है, उनकी न तो बैंकों में साख है और न कपड़ा खरीदने या माल को छुड़ाने की क्षमता है। उन्हें 15, 20 लाख रुपये का कपड़ा बेचा जाता है, लेकिन कपड़ा पहुंचने के बाद न हुंडी छुड़ाई जाती है और न कपड़ा लिया जाता है। परिणाम यह होता है कि मिलों के प्रबन्धकों को कपड़ा वापस लेना पड़ता है।

मेसर्ज राजलक्ष्मी एसोसिएट्स, कलकत्ता को 23 लाख रुपये का कपड़ा भेजा गया। चूंकि दो पैसे दाम बढ़ गया, इसलिए उन्होंने कपड़ा नहीं उठाया। मिल को वह कपड़ा वापस लेना पड़ा और 50 हजार रुपये का डैमरेज देना पड़ा। उसी व्यक्ति को चेयरमैन द्वारा ढाई परसेंट रीबेट दिया गया। इन मिलों में ऐसी धांधलियां बड़े पैमाने पर चल रही हैं।

जब मैसर्ज शक्ति एजेन्सीज, अमृतसर को दिल्ली, यू० पी० तथा पंजाब के लिए कपड़ा बेचा गया, तो इन्दौर हैड क्वार्टर से मिलों को पत्र भेज कर कहा गया कि उन्हें रीबेट दिया जाये। उस पत्र का नम्बर यह है : सेल्ज /2724/78. दिनांक 3-2-78।

माल बेचने की सारी पालिसी चेयरमैन ने अपने हाथ में रखी हुई है। एक गांठ बेचने के लिए भी उनसे पूछना पड़ता है और उन के आदेश के बाद ही सेल्ज मैनेजर माल बेच सकता है। यह भी देखा गया है कि एक गांठ का मूल्य भी वही है और एक हजार गांठों का मूल्य भी वही है। राजनन्दगांव, उज्जैन और भोपाल में प्रबन्धकों को पत्र द्वारा माल बेचने की अनुमति लेनी पड़ती है। इस में एक सप्ताह लग जाता है। कपड़े के दाम घटते-बढ़ते रहते हैं, लेकिन उनकी अनुमति के बिना कपड़ा नहीं बेचा जा सकता है।

इस पालिसी को समाप्त किया जाये। मिल के मैनेजरों को कपड़े का सौदा करने का अधिकार होना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाये कि इन मिलों को घाटा न हो। मध्य प्रदेश की सात मिलों में इस समय चालीस लाख रुपये का कपड़ा जमा है—कोई उसे लेता नहीं है। चेयरमैन की इन नीतियों के कारण मिलों में हड़तालें और वर्कर्ज में झगड़े होते हैं। चेयरमैन इन समस्याओं को सुलझाने में सक्षम नहीं है। मिलों के पास हजार रुपये के माल का पेमेंट करने के लिए भी पैसा नहीं है। इस के लिए उन्हें बैंक का मुंह देखना पड़ता है। वेतन अथवा एडवांस देने के लिए बैंकों के चक्कर काटने पड़ते हैं। बैंक वालों की

अपनी सीमायें हैं और वे पैसा नहीं दे पाते हैं । इस प्रकार वर्कर्ज को वेतन नहीं मिलता है और अफसरों की मारपीट और घेराव होता है। मेरा निवेदन है कि इस सारे मामले की जांच की जाये ।

MR. SPEAKER: You have made a very long statement. Under Rule 377 you can make only a brief statement. आप ने बहुत लम्बा स्टेटमेंट दे दिया है ।

श्री हुकम चन्द कछवाय : मैं अभी खत्म कर रहा हूं । एल पी श्रीवास्तव जो चेयरमैन हैं, यह अभी गए हैं 1977 में, इनकी जो नियुक्ति हुई है उस के बाद से इन्होंने काफी गड़बड़ी वहां की है । इन के खिलाफ सी बी आई एन्क्वायरी कर रही है । एक कोई दीक्षित हैं हेड आफिस दिल्ली के अन्दर, ये बहुत पुराने कांग्रेस के मददगार हैं । पिछले चुनाव में बहुत बड़ी मात्रा में पैसा इकट्ठा कर के इन्होंने कांग्रेस को दिया । आज भी इंदिरा गांधी जब दिल्ली में होती हैं तो वह रोज उन से मिलते हैं । उन की कृपा से बच रहे हैं । मेरा निवेदन है कि इन सारे तथ्यों की जांच कराई जाय । मिलों की स्थिति आज ऐसी हो गई है कि वे कभी भी बन्द हो सकती हैं । अगर मिलें बन्द हो गई तो मध्य प्रदेश के अन्दर 40 हजार लोग बेरोजगार हो जाएंगे । उससे औद्योगिक अशांति भडकेगी और फैलेगी । कपड़ा मिलों में औद्योगिक अशांति अगर फैलेगी तो उससे मध्य प्रदेश के तमाम उद्योगों के अन्दर यह स्थिति पैदा होगी ।

मैंने जो बातें आप से कही हैं उन को आप मंत्री महोदय तक भेजवा दें । मंत्री महोदय को मैं दो बार विस्तार में पत्र लिख चुका हूं लेकिन उन का अभी तक जवाब नहीं आया । एक पत्र मिला था कि जांच करवा रहे हैं लेकिन उस के बाद और पत्र मैंने भेजे हैं, उन का जवाब नहीं मिला है । मैं चाहता हूं कि मैंने कालिंग अटेंशन दिया है, उसे आप स्वीकार कर लें ताकि मंत्री महोदय और बातों पर भी प्रकाश डाल सकें ।

(iv) FORMATION OF A NEW RAILWAY DIVISION OF SOUTHERN RAILWAY IN KERALA

SHRI A. SUNNA SAHIB (Palghat): The Minister of Railways announced during his Railway Budget speech that a new division would soon be formed with Trivandrum as headquarters in the Southern Railways. This announcement has caused deep resentment among the people of all sections and the employees of Railways in the Olavakkot Division, which is at present the only Division in Kerala. Olavakkot Division has been functioning effectively and economically during the past 21 years, forging unity among the people of North Kerala and of the erstwhile princely States of Trivandrum and Cochin.

Now, firstly, the creation of Trivandrum Division will break this unity among the people of Kerala. Secondly, for the formation of Trivandrum Division, a large part of the present Olavakkot Division has to be taken away, which will inevitably affect greatly the economic functioning of both Olavakkot and Trivandrum Divisions. Thirdly, there will be great dissatisfaction and resentment among the Railway employees of the Olavakkot Division. Fourthly, the industries of North Kerala will be seriously affected as they will be made to run to Trivandrum every now and then. Fifthly, the Railway Minister has himself been apprised of the problems arising out of this proposal by a delegation of eminent public men and trade union leaders of North Kerala. They have given him complete details of the Olavakkot Division how it was originally form-